(a) the amount spent on the building 'Yogakshema,' the headquarters of the Life Insurance Corporation at Bombay;

(b) in how many years the building was completed; and

(c) whether the work was got done through private contractors; if so, through whom?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI) : Rs. 11450 lakhs approximately.

(b) Four years and one month.

(c) Yes. The names of the more important contractors are indicated below:

(1) M|s. Shah Construct'on Company
(2) M/s Mckenzies
(3) M/s E'ectrical Construction & Equipment Co.
(4) M]s. Bamboat & Co.
(5) M/s MAN Industrial Corporation
(6) M/s Chippendale
(7) M/s Otis Elevators Co.
(8) M/s Haldankar Engineers
(9) M/s Prmier Lighting Co. Pvt. Ltd.
(10) M/s Aireonditioning Corporation
(11) M/s Gupta Tiles and Marble
(12) M/s Cole Paint & Construction Co.
(13) M/s. India Water-proofing Co.
(14) M/s. Jay Engineering Works
(15) M/s Oriental General Agencies
(16) M/s Bajaj Electricals Ltd.
(17) M/s Pest Control M. Walshe
(18) *U/s* Shilp-i
(19) M/s Voltas
(20) M/s Umrigar & Co.
(21) M/s Modern Glass Mart
(22) M/s L. Kant & Co.
(23) M/s Glo-light Electricals
(24) M/s Tayabi & Co.
(25) M/s Naginlal Keshavlal & Co.
(26) M/s Shubhadwar Rolling Shutters
(27) M/s Greaves Cotton & Crompton Parkinson
(28) M/s Mistry Ebrahim Suleman & Co.

चीजों के मूल्य में वृद्धि

२०८. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न चीजों के जो मूल्य बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई नये उपाय निकाले हैं ; और यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

t [RISE IN PRICES OF COMMODITIES

208. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether Government have devised any new measures to check the rise in prices of various commodities in the country, and if so, what are those measures?).

वित्त मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सभा में लगा है जिसमें यह बताया गया है कि सरकार ने मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये हाल के महीनों में कौन से उपाय किये हैं ।

विवरण

हाल के महीनों में कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए नीचे लिखे उपाय किये गये हैं :

(१) गेहूं की कीमतों को बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सस्ते अनाज की और दुकानें (फेयर प्राइस शाप्स) खोलें, इन दुकानों के जरिये गेहूं और आटे की सप्लाई की व्यवस्था करें और चक्कियों को और अधिक मात्रा में गेहूं दें । आटा पीसने की चक्कियों से कहा गया है कि वे अपनी पूरी क्षमता से काम करें ।

(२) सस्ते अनाज की दुकानों की संख्या, जो सितम्बर, १९६३ के अन्त में ५५,२५८ थी, बढ़ा कर दिसम्बर १९६३ के अन्त तक ६०,२७८ कर दी गयी । केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजना के अनुसार खोले गये थोक उपभोक्ता सहकारिता भण्डारों (होलसेल कन्ज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स) की संख्या, जो अक्तूबर १९६३ के अंत में १३१ थी, बढ़कर दिसम्बर १९६३ के अंत में १४३ हो गयी और इसी अवधि में इस योजना के अनुसार चल रहे प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों/शाखाओं की संख्या २,०४६ से बढ़कर २,३४१ हो गयी ।

(३) केन्द्रीय स्टाक से अधिक गेहूं दिया जा रहा है और राज्य सरकारों की आवश्यकता पूरी की जा रही है । हाल के महीनों में मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और केरल राज्यों में चावल का भी अधिक मात्रा में वितरण किया गया है ।

(४) १९६३ की आखिरी तिमाही में, इससे पहले के वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले चावल और गेहूं दोनों का अधिक मात्रा में आयात किया गया । जनवरी से मार्च १९६४ तक की चालू तिमाही में भी १९६३ की पहली तिमाही की अपेक्षा इन दोनों अनाजों का अधिक आयात किया जाने का अनुमान है । चालू वर्ष में और अधिक आयात करने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(५) रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को आदेश दिया है कि वे जनवरी-फरवरी १९६४ से हर दो महीनों की अवधि में धान और चावल के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों की उच्चतम सीमा को, १९६२ की इसी अवधि में इन वस्तुओं के लिए दिये गय औसत अग्रिमों के ९० प्रतिशत तक ही सीमित रखें । गोदामों की रसीदों के आधार पर दिये जाने वाले अग्रिमों से भिन्न अग्रिमों के लिए इस सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत एक अलग सीमा निर्धारित की गई है ।

(६) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे लाइसेंसशुदा थोक व्यापारियों पर कुछ और पाबंदियां लगायें । इन व्यापारियों को अपनी कुल बिक्री के अनुसार ५०० रुपये से १००० रुपये तक की रकम जमानत के तौर पर जमा करानी पड़ती है, उनके द्वारा सूचित स्थानों पर अनाज का संग्रह करना पड़ता है, अपनी दुकानों पर मूल्य-सूची लगानी पड़ती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उन्हीं खुदरा व्यापारियों के हाथ चीजें बेचनी पड़ती हैं जिनके नाम उनके पास रजिस्टर किये गये हों ।

(७) इस उद्देश्य से कि चालू मौसम में चीनी का उत्पादन अधिक से अधिक हो । १९६१-६२ के मुकाबले १९६३-६४ में चीनी के कारखाने जितना अतिरिक्त उत्पादन करेंगे, उस पर उन्हें उत्पादन शुल्क में कुछ छूट दी जायगी । गन्ना पेरने के मुख्य मौसम में किये गये अतिरिक्त उत्पादन पर २० प्रतिशत और १९६३-६४ के मौसम के शुरू के और आखिरी हिस्से में किये गये अतिरिक्त उत्पादन पर ५० प्रतिशत छूट दी जायगी । जहां तक नये कारखानों का संबंध है, उनके १९६१-६२ के वास्तविक या अनुमित उत्पादन के मुकाबले जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उस पर उत्पादन-शुल्क में ३० प्रतिशत की सामान्य दर से छूट दी जायगी ।

(८) चीनी के कारखानों द्वारा उस गन्ने के लिये दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य, जिससे ९ प्रतिशत हो प्राप्ति हो, बढ़ाकर, ४.६९ रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया जब कि १९६२-६३ के मौसम के लिये निर्धारित न्यूनतम मूल्य ४.०२ रुपया प्रति क्विंटल था । चीनी के ऐसे कारखानों को, जो या तो उन इलाकों में हैं जहां बहुत अर्से से गुड़ बनाया जाता है या जो विशेष परिस्थिति वाले क्षेत्रों में हैं, यह इजाजत दे दी गयी कि वे गन्ने का मूल्य ५.३६ रुपया

प्रति क्विंटल दे सकते हैं । इन कारखानों में बनी चीनी के कारखाना निकलते मूल्य में भी तदनुरूप वृद्धि कर दी गयी है । ये उपाय इस उद्देश्य से किये गए कि चीनी के कारखानों को अधिक मात्रा में गन्ना मिले ।

(६) वनास्पती के अधिकतम मूल्य निर्धारित किये जाते हैं और कच्चे तेलों के मूल्यों की घट-बढ़ के अनुसार उनमें भी समय समय पर घट-बढ़ की जाती है ।

Tm MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI) : A statement showing the measures taken by Govrnment in recent months to check the rise in prices is attached.

STATEMENT

The following measures have been taken to check the rise in prices in recent months:

(1) With a view to keeping a check on wheat prices, the State Governments have been asked to open new fair price shops, arrange supplies of wheat and wheat atta through these shops and step up distribution of wheat to Chakkies. The roller flour mills have been asked to work to their full capacity.

(2) The number of fair price shops increased from 55,258 at the end of September 1963 to 60,278 at the end of December 1963. The number of wholesale consumer co-operative stores organised under the Centrally sponsored scheme went up from 131 at the end of October 1963 to 143 at the end of December 1963 and the number of primary consumer stores branches operating under the same scheme from 2,046 to 2,341 during the same period.

(3) Issues of wheat from the Central Stock have been stepped up **and** the State Governments' requirements are being met fully. The distribution of rice has also been increased in recent months, in the States of Madras, Andhn Pradesh and Kerala.

†[ ] English translation.

(4) Larger quantities of both rice and wheat were imported during the last quarter of 1963 than in the corresponding quarter of the preceding year. During the current quarter—. January to March 1964—also, imports of both these foodgrains are expected to be larger than in the first quarter of 1963. Arrangements are being made for additional imports during the current year.

(5) The Reserve Bank has directed the scheduled banks to keep their advances against paddy and rice during each two-month period beginning January-February 1964 within a ceiling of 90 per cent, of the average of their advances against these commodities during the corresponding period of 1962. A separate ceiling has been fixed within the overall ceiling for advances other than those against warehouse receipts.

(6) The State Governments have been advised to impose certain additional conditions on licensed wholesale dealers. The dealers are required to furnish a security deposit of Rs. 500 to 1,000 depending on their turnover, maintain storage of foodgrains at places declared by them, exhibit prices at their shops and make sales only to retailers registered with them and jn accordance with the directives issued by the competent authority from time to time.

(7) With a view to maximising the output of sugar in the current season, the sugar factories have been allowed a rebate in excise duty on additional output of sugar in 1963-64 over 1961-62. The rebate will b_e 20 per cent, in respect of excess production in the main crushing period and 50 per cent, in respect of excess output during tne early and the latter part of the 1963-64 season. In respect of new units, the excise duty rebate will be calculated at a flat rate of 30 ner cent, on production in excess of their actual or notional output in 1961-62.

(8) Th$_e$ minimum price of sugarcane payable by the sugar factories was increased to Rs. 4-69 per quintal linked to a recovery of 9 per cent, as against the minimum price of Rs. 4:02 per quintal fixed for the 1962-63 season. ISugar factories in traditional gur producing areas or in areas where special circumstances existed were permitted to pay a price of Rs. 5 '36 per quintal of cane. The ex-factory sugar price of these factories has also been stepped up correspondingly. These measures were taken to increase the supply of sugarcane to the sugar factories.

(9) Maximum prices of vanaspati are fixed and they are varied from time to time depending on the changes in the prices of raw oils.]

ALLOTMENT OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION TO LADY GOVERNMENT *SERVANTS*

209. SHRI J. H. JOSHI: Will the Minister of WORKS. HOUSING AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether any concessions are given to lady Government Servants in the matter of allotment of Government residential accommodation;

(b) if so, what are those concessions; and

(c) the number of ladies who appli ed for allotment and the number of those who were provided Govern ment accommodation during the last five years?

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND REHABILITATION (SHIU MEHR CHAND KHANNA) ; (a) to (c) Lady Government servants are eligible for allotment of residential accommodation from the general pool like male Government officers. In addition, a Lady Officers' Pool of 475 residences has been created. 389 ladies are actually occupying accommodation in this pool and 230 are awaiting allotment. Separate lists are not maintained for lady applicants who apply for allotment out of the general pool. Information about the total number oi ladies who applied for allotment during the last 5 years and those who were provided Government accommodation during that period is, therefore, not available and the time and labour involved in collecting this information wiH not be commensurate with the results likely to be achieved.

210. [Transferred to *the* 5th *March,* 1964].

ECONOMIC COOPERATION BETWEEN INDIA AND JAPAN

211. SHRI SITARAM JAIPURIA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether recently any discussion took place between the Planning Commission and some Japanese official regarding economic co-operation between India and Japan; and

(b) if so, what was the nature of the discussion?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B. R. BHAGAT): (a) No.

(b) Does not arise.

EXPORT OF CURRY POWDER

212. SHRI KRISHAN DUTT: Will the Minister of INTERNATIONAL TRADE be pleased to state the action taken by Government on the recommenda tions made by the Spices Trade Dele gation sponsored by the Spices Expo t Promotion Council regarding removal of handicaps in the way of export of Indian curry powder?

THE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE (SHRI MANTTBHAI SHAH): A Special Export Promotion Scheme to provide the required facilities for stepping up the export of spices is under Government's consideration. Under this scheme, imports of modern grinding machinery, packing material tnd exotic spices to boost up export of curry powder are proposed to be eorered.